**श्री वीर सिंह :** छोटे स्टेट होने से न्याय मिलेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mahendra Singh Mahra.

**Demand for increasing gas supply to Uttarakhand**

**श्री महेन्द्रसिंह माहरा** (उत्तराखंड) **:** माननीय उपसभापति जी, उत्तराखंड प्रदेश 1 करोड़, 20 लाख की आबादी वाला प्रदेश है। **...(व्यवधान)...**

**श्री के.सी. त्यागी :** इससे तो हमें **...(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति :** आप बैठिए त्यागी जी। **...(व्यवधान)...**

**श्री महेन्द्र सिंह माहरा :** आज उत्तराखंड गैस और मिट्टी के तेल की भारी कमी के कारण परेशानी से जूझ रहा है। मान्यवर, यदि उत्तराखंड का भूगोल देखें, तो 13 ज़िलों में से 10 ज़िले पहाड़ी क्षेत्रों के हैं और संपूर्ण उत्तराखंड 65 परसेंट जंगल से घिरा हुआ है, परंतु आज हमें जलाने की लकड़ी के लिए तरसना पड़ता है। आज यदि रोटी बनाने के लिए हम लकड़ी काटना चाहें, तो नहीं काट सकते हैं। उत्तराखंड में केरोसीन का जो कोटा नई सरकार ने कम किया है, जो कि पिछली सरकार के समय में 9,913 किलोलीटर था, इस सरकार ने, केन्द्र की नई सरकार ने उसको काटकर 2972 किलोलीटर कर दिया है। यानी 6941 किलोलीटर केरोसीन कम कर दिया गया है। मान्यवर, प्रदेश में गैस के कनेक्शन कम करने के बाद लोगों को पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस दिन तक लाइन में खड़े होना पड़ता है और वे गैस लिए बिना ही घर वापस चले जाते हैं। सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था चौपट है, सारी प्रणाली फेल हो चुकी है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, बैंकों में खाते नहीं खुल पा रहे हैं और स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। मान्यवर, उत्तराखंड के दस ज़िले, जो पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्र में हैं, उन कई ज़िलों की सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, इस विस्फोटक स्थिति के कारण रोजाना सड़कों पर जाम लगता है और रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि राज्य में गैस और केरोसिन तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए; ऑनलाइन व्यवस्था और आधार कार्ड को ठीक कराया जाए एवं बैंक में खाते शीघ्र खुलवाए जाएं। धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**Reported caste discrimination among school children**

**डा. विजयलक्ष्मी साधौ** (मध्य प्रदेश) **:** सर, यह मेरा सौभाग्य है कि आज प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हुए हैं और मैं उन्हीं के स्लोगन से अपनी शून्यकाल की बात की शुरुआत करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है "सबका साथ, सबका विकास" और "मेक इन इंडिया"। मैं उनसे

[डा. विजयलक्ष्मी साधौ]

यह पूछना चाहती हूं, आपसे यह पूछने की गुस्ताखी कर रही हूं कि यह कैसा सबका साथ है, कैसा सबका विकास है और कैसा मेक इन इंडिया है? 6 दिसम्बर, 2014 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में किसी एजेंसी के द्वारा एक सर्वे किया गया। इसने जो रिपोर्ट दी है, उसके माध्यम से यह बताया गया है कि देश के जो नौनिहाल हैं, जिसमें आप सबका साथ चाहते हैं, उन नौनिहालों की क्या गलती है कि वे दलित परिवारों में पैदा हुए हैं? आप भी मध्य प्रदेश के कई गांवों के अन्दर इन नौनिहालों के साथ स्कूलों में अध्यापकों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। मैं रिपोर्ट के आधार पर आपसे यह कहना चाहती हूं, यह हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश स्टेट है, जिसकी इमेज ऐसी बनाई जाती है कि Madhya Pradesh is one of the fastest growing States और दूसरी तरफ बच्चों को स्कूलों में मिड डे भोजन में मजबूर किया जाता है कि उन-उन बर्तनों में वे खाना खाएं, जिनमें उनके नाम खुदे हुए हैं। उनको अलग लाइन में बिठाया जाता है, उनके लिए अलग पानी की व्यवस्था की जाती है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह सर्वे रिपोर्ट कह रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह कैसा विकास है, किसका विकास है? आप कैसे मेक इन इंडिया की कल्पना कर रहे हैं? क्यों एक कम्युनिटी के लोगों को अलग रखा जा रहा है? उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है?

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है, जहां की ज्यादातर आबादी आदिवासी और दलितों की है। वहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप तभी दी जाएगी, जब वे फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराएंगे। इसमें लिखा है कि "In Dahi village of Dhar district, Dalit school kids are told that they would get scholarships only after they produce photographs of family members skinning dead animals, considered their traditional occupation. यह क्या हो रहा है! ये क्या दर्शा रहे हैं! ये क्या कह रहे हैं! कथावा विलेज छत्तरपुर, मध्य प्रदेश का विलेज है, यहां पर वे पानी के मटके लेकर चले आ रहे हैं। **...(समय की घंटी)...** वह भी अध्यापक के द्वारा! यह कैसा मेक इन इंडिया है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. ...*(Interruptions)*...

**श्रीमती विप्लव ठाकुर** (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

**श्री मोती लाल वोरा** (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

**श्री वी. हनुमंत राव** (तेलंगाना) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

**श्रीमती कहकशां परवीन** (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associate with the issue raised by the hon. Member. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Santiuse Kujur. ...*(Interruptions)*...

**Discontinuation of supply of subsidised food grains by F.C.I. to tea garden plantation workers in Assam**

SHRI SANTIUSE KUJUR (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to raise the ...*(Interruptions)*... issue of discontinuation of supply of subsidised foodgrains to tea garden workers in Assam.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the subsidised foodgrain distribution scheme has been in operation in tea estates of Assam since Independence. The allocation is made by the Central Government and State Government through Food Corporation of India. The tea garden workers and their dependants have been benefiting for more than 65 years and the tea garden managements have been successfully implementing the scheme.

The scheme is being implemented uniformly regardless of transport connectivity of tea gardens particularly in the remote areas and recurring flood-affected areas. There are almost 1000 tea gardens across the State of Assam. It requires approximately 12,700 metric tonnes of foodgrains per month for supply to the tea estate workers. About 25 lakh tea garden population is benefited from this scheme.

Now I have come to know that the foodgrain supply would be discontinued from January 2015. As a result, there is uncertainty and unrest in the minds of tea workers. Protests and agitation are going on in the tea gardens demanding distribution of foodgrain amongst the tea workers through the present system.